International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

भारत में गठबंधन की राजनीति में स्थायी एवं अस्थाई सरकारों का अध्ययन।

सुषमा कुमारी

(शोध-छात्रा) राजनीति विज्ञान विभाग

बी. आर. ए. बी. यू विश्वविद्यालय

मुजफ्फरपुर, बिहार, भारत

डॉ हरिश्वचंद्र प्रसाद यादव

शोध निर्देशक, प्रो.व. विभाग अध्यक्ष

राम मनोहर लोहिया स्मारक महाविद्यालय मुजफ्फरपुर, बिहार ,भारत

शोध सारांश-

भारतीय संविधान के अनुसार भारत में संघीय व्यवस्था है।जहां पर केंद्र स्तर पर सरकार दिल्ली में है तथा विभिन्न राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में राज्य सरकार है। इसलिए भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य (क्षेत्रीय) स्तर पर राजनीतिक दलों का वर्गीकरण उनके क्षेत्र में उनके प्रभुत्व के अनुसार किया जाता है। भारत में बहुदलीय पार्टी वे है जो चार या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। उन्हें यह अधिकार भारत के चुनाव आयोग द्वारा प्राप्त होता है। जो विभिन्न राज्यों में समय-समय पर चुनाव परिणाम की समीक्षा करते हैं। भारत में राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच करी के रूप में कार्य करते हैं। क्षेत्रीय दल एक मध्यस्थता का कार्य करने के साथ ही एक छोटे से समाज में निर्मित राजनीतिक दल समाज के सहयोग में एक बड़ा रूप धारण करता है सरकार बनाकर सत्ता को संभालते हैं इसलिए यह कहना सत्य है की राजनीति दल सरकार और जनता के बीच सक्रिय भूमिका निभाते हुए जनता और सरकार को जोड़ने का कार्य करते हैं।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद :-

According to the Indian Constitution, India has a federal system where the central government operates at the national level in Delhi, and state governments function in various states and

union territories. Therefore, political parties in India are classified as national and state (regional) parties based on their dominance and influence in specific regions.

India follows a multi-party system, where smaller regional parties play a significant role. A national party is one that is recognized in four or more states. This recognition is granted by the Election Commission of India, which reviews election results from time to time in various states.

Political parties act as a link between the government and the public. Regional parties not only act as intermediaries but also grow from small community-based political groups into larger influential entities, sometimes even forming governments and holding power. Therefore, it is true to say that political parties play an active role in connecting the public and the government, facilitating communication and representation between them.

According to the Indian Constitution, India has a federal system where the central government operates at the national level in Delhi, and state governments function in various states and union territories. Therefore, political parties in India are classified as national and state (regional) parties based on their dominance and influence in specific regions.

India follows a multi-party system, where smaller regional parties play a significant role. A national party is one that is recognized in four or more states. This recognition is granted by the Election Commission of India, which reviews election results from time to time in various states.

Political parties act as a link between the government and the public. Regional parties not only act as intermediaries but also grow from small community-based political groups into larger influential entities, sometimes even forming governments and holding power. Therefore, it is true to say that political parties play an active role in connecting the public and the government, facilitating communication and representation between them.

मुख्य शब्द -भारत ,राजनीति पार्टी, गठबंधन ,क्षत्रिय दल, चुनाव ,अस्थाई

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवादक- Bharat, Politicalparty, Coalltion, Regional party, Election

प्रस्तावना

लोकतंत्र की व्यवस्था में सरकारों का आशय यही रहता है कि "सरकार एक निश्चित कार्यकाल में राजनीतिक स्थायित्व बनाए रखें। जो सरकार का पहला तत्व होता है। लेकिन स्थायित्व एक ऐसी प्रक्रिया है जो सरकार के निश्चित कार्यकाल तक बने रहने का है। जो सही मायने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर सत्ता प्राप्त करती है। और यह सरकार लोकतंत्र के आधार पर ही फैसला लेती है एवं उसे सत्ता में वैधता प्रदान करती है। लोकतंत्र की प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार का आशय होता है प्रभावपूर्ण शासन बनाना।

राजनीतिक अस्थायित्व का आशय है कि बार-बार और जल्दी-जल्दी होने वाली सत्ता परिवर्तन इसका मुख्य कारण है। लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य भी स्थितियां है जो विभिन्न मात्रा में राजनीतिक अस्थायित्व को जन्म देती है। गठबंधन के दौर में बनने वाली सरकार में राजनीतिक अस्थायित्व का गुण सदैव विद्यमान रहता है। केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्य में मुख्यमंत्री के द्वारा राजनीतिक कार्यों में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था में बार-बार किए जाने वाले परिवर्तन से गंभीर विवाद सरकार को अस्थाई की ओर ले जाने का प्रमुख कारण होता है। इसमें सरकार द्वारा राजनीतिक संयंत्र को अपना कर शासन सम्यक सांसदों एवं विधायकों की संख्या बदलने वाली घटना इस प्रकार राजनीतिक अस्थाई को जन्म देती है। भारतीय राजव्यवस्था में गठबंधन की सरकार एक आदत सी बनती जा रही है जिसके कारण अस्थायित्व की सरकार बनती है।

अस्थायित्व सरकारें

केंद्रीय स्तर की राजनीति में गठबंधन के दौर में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वप्रथम 1970 में गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी थी। यह पहली सरकार थी जो एक दलीय सरकार की प्रथा को तोड़कर गठबंधन सरकार बनाई थी। जो संपूर्ण रूप से गठबंधन की सरकार रही, लेकिन 1969 में मोरारजी देसाई सरकार का विघटन हो गया। जो भारत की राजनीति में पहले अस्थाई सरकार का प्रयोग सिद्ध हुआ और यह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका एवं इस सरकार का पतन के साथ भारत में परिवर्तन का दौर की शुरुआत हुई, लेकिन शुरुआत होते ही समाप्त भी हो गया। लेकिन सही मायने में 1970 की गैर कांग्रेसी सरकार सच में एक क्रांति ही थी। जिसे 30 वर्ष के एक दलीय क्षत्र को खत्म कर दिया।केंद्रीय राजनीति में मोरारजी देसाई का विखंडन 1979 में हुआ जिसका कारण था जनता पार्टी संस्था विन्यासित न होकर व्यक्ति विन्यासित बनी रही। जनता पार्टी में जिंन दालों ने अपना विलय किया वह अपने धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों को छोड़ नहीं पाए थे।जनता पार्टी के विभिन्न घटकों में घटकवाद और दल बदल तथा केंद्र से लेकर

राज्य स्तर की विभिन्न घटकों ने नेताओं के बीच जो खींचतान हुआ। उसमें ना तो संवैधानिक संघवाद को महत्व मिला, ना प्रांतीय स्वच्छता के अनुसंधीय मूल्यों को ना गठबंधन मानकों को अंतत जनता पार्टी 28 माह बाद बिखर गई।

मोरारजी देसाई की सरकार के पतन के बाद कांग्रेस ने बाहरी समर्थन से चौधरी चरण सिंह को 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। लेकिन 20 अगस्त 1989 को अपना विश्वास मत प्राप्त ही नहीं करने के कारण प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देना पड़ा इसी घटना के दौरान जनता पार्टी के सरकार में अस्थायित्व का वातावरण व्याप्त रहा। जिस कारण से जनता ने फिर से इस सरकार पर भरोसा नहीं दिखाई।

भारतीय राजनीति में 80 के दशक में फिर एक दलीय शासन का बनाना आश्चर्य का विषय था। क्योंकि जिन कारणों से 70 के अंतिम समय तक कांग्रेस सत्ता से दूर हुई उससे यह स्पष्ट हुआ कि कांग्रेस के पुनः सत्ता में आने में समय लगेगा। लेकिन 80 के दशक के शुरुआत में कांग्रेस की वापसी ने पुनः एक बार फिर एक दलीय सरकार का जिक्र करना अति आवश्यक बना दिया। चुनाव में इंदिरा गांधी पुनः एक बार प्रधानमंत्री का कार्य भार संभाला ।लेकिन यह समय वैसा नहीं था। जो 1971 से 77 के बीच मे रहा।यह कार्यकाल कुछ अपवादों को छोड़कर देखा जाए तो ठीक-ठाक ही चला। लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या उनके सुरक्षाकर्मियों द्वारा करने से पूरे देश में दुख का लहर फैल गया। अचानक इंदिरा गांधी की मृत्यु से पूरे देश में विराम की स्थिति बन गई। लेकिन राजीव गांधी को जल्दीबाजी में प्रधानमंत्री के पद के लिए शपथ दिलाया गया। पंजाब को इंदिरा गांधी की हत्या का दोषी ठहराया गया।

भारतीय राजनीति में ऐसा कोई आम चुनाव नहीं था। जो 1985 का आम चुनाव था क्योंकि इस चुनाव में प्रभावपूर्ण प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की मृत्यु से भारतीय जनता में एक भावनात्मक लहर उमड़ गए। जिस कारण से इस चुनाव में राष्ट्रीय कांग्रेस को उम्मीद से कहीं ज्यादा सीटें प्राप्त हुई। यही वह चुनाव था जिसमें कांग्रेस को 404 सीट प्राप्त हुई थी। और राजीव गांधी को पुनः प्रधानमंत्री बनाया गया।

1980 से 1989 तक लगभग 10 वर्षों भारतीय राजनीति में केंद्र स्तर पर स्थाई सरकार बनी रही।लेकिन 1989 में कांग्रेस का पतन आरंभ होना शुरू हो गया और भाजपा का उत्कर्ष का समय आरंभ हो गया । और यही से फिर से अस्थाई का दौर शुरू हो गया ।

नवमी लोकसभा चुनाव में 543 सीटों में से 528 सीटों पर चुनाव कराया गया इस समय से एक दलीय सरकार की समाप्ति और मिली जुली सरकार का योग आरंभ हुआ जिसमें भारत की राजनीति में राजनीतिक

स्थायित्व के जगह पर अस्तित्व का उदय हुआ। चौधरी देवीलाल के प्रयासों से 1988 में जनता पार्टी का गठन किया गया। जिसमें बी.पी सिंह को मिलाकर इंडिया गठबंधन बना। संसदीय बैठक में चौधरी देवीलाल को दल का नेता चुना गया। लेकिन वह बी.पी.सिंह के आग्रह करने पर उन्होंने बी.पी.सिंह को प्रस्तावित कर दिया। और सभी सदस्यों ने इसका अनुमोदन भी कर दिया। लेकिन चंद्रशेखर सिंह जी चाहते थे कि उनका नाम प्रस्तावित किया जाएगा। लेकिन वी.पी सिंह का नाम प्रस्तावित होने से वह बहुत नाराज हो गए और बैठक से उठकर चले गए।

दिसंबर 1989 में बी.पी.सिंह सरकार का गठन हुआ। जिसके साथ ही राजनीतिक अस्थायित्व का दौर शुरू हो गया।जिसका परिणाम हुआ की 11 महीने में ही बीपी सिंह की सरकार को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर गिरा दी गई। इस गठबंधन में भी राजनीतिक अर्थव्यवस्था औरअस्थायित्व का दौर देखने को मिला। इसके बाद 60 सांसदों को लेकर चंद्रशेखर ने सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास दावा किया। इसमें कांग्रेस ने बाहर से समर्थन किया। यह सरकार भी एक अस्थाई सरकार ही रहा। और यह सरकार ज्यादा दिन तक सत्ता में नहीं रह सकी।

जनता दल की शक्ति में 1991 में आम चुनाव में भारी कमी आ गई। इस चुनाव में जनता दल को मात्र 35 स्थान पर ही सफलता प्राप्त हुई और इसके बाद दल में एकता कायम नहीं रह सकी अनेक सदस्य ने जनता दल छोड़ दिया। और बाद में अजीत सिंह और उसके समर्थक कांग्रेस (ई)में मिल गए। इस चुनाव में 9 राष्ट्रीय दल 39 राज्य दल और एक 301 रजिस्टर्ड दलों ने भाग लिया। यह पहला ऐसा चुनाव था। जिससे जवाहरलाल नेहरू जी के परिवार से कोई सदस्य ने चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन राजीव गांधी की मृत्यु के कारण जनता की सहानुभूति कांग्रेस के पक्ष में हुआ परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस को जो जनाधार और सीटे चाहिए था वह आंकड़ा पूरा हुआ। और नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया गया। इस चुनाव में जनता पार्टी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ और विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी साबित हुई। यही से इस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर उभरा एवं राजनीतिक में एक अलग दौर की शुरुआत देखने को मिला। यह ऐसी सरकार थी जो अपना कार्यकाल को पूरा करने में सफल रहे।

11वीं लोकसभा चुनाव 1996 में हुआ और त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति बन गई। इससे आने वाले दो सालों में राजनीति में अस्थिरता का माहौल रहा और तीन प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा एक तीसरा संयुक्त मोर्चा अस्तित्व में आए। संसद में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के अटल बिहारी वाजपेई ने प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला लेकिन समर्थन नहीं जुटा पाने के कारण करण 13 दिनों के बाद ही

उनकी सरकार गिर गई। इसके पश्चात जनता दल के नेता एचडी देवगौड़ा ने संयुक्त मोर्चा गठबंधन सरकार का गठन कर 1 जून 1996 को प्रधानमंत्री पद संभाला। उनकी सरकार 11 महीने ही चली। इसके बाद 21 अप्रैल 1997 को इंद्र कुमार गुजराल तीसरे प्रधानमंत्री बने। दो साल तक राजनीतिक अस्थिरता के बाद 1998 में पून:लोकसभा चुनाव हुआ। चुनाव में सबसे अधिक सीट मिलने वाली भाजपा को संयुक्त बिहार में 32 उम्मीदवार में 18 एवं कांग्रेस के 54 उम्मीदवार में मात्र दो उम्मीदवार जीते। जनता दल के 44 उम्मीदवारों में से में 22 उम्मीदवार को सफलता मिली। लेकिन सरकार में सहायक घटक दलों की समय-समय पर छोटी-छोटी मांगों को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न होने लगी। जिससे सरकार की स्थिरता पर सवाल उठने लगे। यहां यह देखने को मिला है कि गठबंधन से बनी सरकार का जीवन का कोई भी भरोसा नहीं होता है। वह अपना कार्यकाल पूरा कर सकेगी या गिर जाएगी यह भी एक अस्थाई सरकार सिद्ध हुई।

विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों के बीच आपसी गठबंधन न होने के कारण अंत में 26 अप्रैल 1999 को विघटित कर दिया गया। और अगले चुनाव की घोषणा कर दी गई। 26 अप्रैल 1999 को 12वीं लोकसभा चुनाव होने के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी गठबंधन बनाने के लिए जोड़-तोड़ करना शुरू हो गया। 13वीं लोकसभा के लिए भाजपा ने कुछ क्षेत्रीय दलों के दलों से चुनावी समझौता किया। और एनडीए बनाया। और इसी के तहत कार्य आरंभ किया। भाजपा के इस आम चुनाव में केवल 239 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े की। कांग्रेस ने 453 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन फिर भी कांग्रेस की पार्टी चुनाव में अपना सीट नहीं ला सका और कांग्रेस को भारी नुकसान सहना पड़ा। और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आया इस चुनाव में भाजपा के गठबंधन को 297 सीट एवं कांग्रेस को 136 सीट प्राप्त हुई और अन्य को 108 सीट प्राप्त हुई। लोक सभा में सबसे बड़ी राजनीतिक दल भाजपा अपने सहयोगी दालों के साथ मिलकर सरकार बनाने में सफल रहा। सरकार एक बार फिर से पून:अटल बिहारी के नेतृत्व में बनी। जो अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले 8 महीने पहले ही भांग हो गए।

भारतीय राजनीति में स्थायित्व की सरकार

भारतीय राजनीति में गठबंधन का ऐसा योग आरंभ हुआ जो देश में एक नया क्रांति का आगाज हुआ। और यह क्रांति गठबंधन के कारण संभव हुआ।14वीं लोकसभा चुनाव से पहले जितनी भी सरकारी बनी। चाहे वह गठबंधन की ही ना क्यों हो। यह सभी गठबंधन चुनाव के बाद जोड़-तोड़कर आपसी सहयोग से सरकार बनती है। फिर भी वह सरकार स्थायी सरकार नहीं बन पाई। लेकिन कांग्रेस 2004 के आम चुनाव के शुरुआत से पहले ही यूपीए का निर्माण किया था। (यूनाइटेड संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) इस UPA गठबंधन में अनेक

क्षेत्रीय दल एवं राज्य स्तरीय दलों को शामिल किया गया। जबकि भाजपा ने 1999 में आम चुनाव से पहले ही एनडीए का निर्माण क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय पार्टी को मिलाकर कर चुके थे।

13वीं लोकसभा को 8 महीने पहले यानी की 8 फरवरी 2004 को ही भंग कर दिया। और साथ ही 14 वी. लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दिया गया।अटल बिहारी वाजपेई सरकार द्वारा सरकार को समय से पहले ही भंग करने का निर्णय सत्तारूढ दल के द्वारा चौथी बार लिया गया। भाजपा ने अपने गठबंधन में 24 दलों को लेकर गठबंधन का निर्माण अटल बिहारी वाजपेई के नेतृत्व में हुआ। इस चुनाव में UPA को सत्ता प्राप्त हुआ। और यूपीए ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। यह कार्यकाल इतना प्रभावित रहा कि इसके कुछ वादों को छोड़कर देखा जाए तो डा.मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनमानस के लिए ऐसे ऐसे कार्य किया। जिसमें भारत ने एक नई क्रांति ला दिया ,2005 में सूचना का अधिकार और ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे पलायन को रोकने एवं बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना तो ग्रामीण के लिए जीवनदान साबित हुई।

एक बार फिर से 15 वी. लोकसभा चुनाव में UPA- 2 की ही सरकार बनी। भले ही यह सरकार गठबंधन की ही रही हो लेकिन स्थायित्व सरकार होने का जो गौरव प्राप्त हुआ वह पहले की सरकार जैसा नहीं रह गया था जिसमें सरकारे अल्पअवधि की ही हुआ करती थी। उसे मानवीय राजनीति में संकट का दौर ही कहा जा सकता है। 2009 के आम चुनाव से पहले ही गठबंधन के द्वारा गठबंधन में दरार देखने को मिली जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आते गए सहयोगी दलों के संबंधों में तेजी से परिवर्तन देखने को मिला। जिसका परिणाम हुआ कि लालू प्रसाद यादव (राजद) ,रामविलास पासवान (लोजपा) अलग हो गए। लेकिन इस सरकार का एक सकारात्मक परिणाम यह रहा कि यूपीए- 1 और यूपीए- 2 ने जिस क्षेत्रीय दलों को लेकर सरकार बनायी उस पार्टी को सरकार में स्थान दिया और उन क्षेत्रों के विकास को लेकर तत्परता से कार्य किया जिसका लाभ क्षेत्रीय दलों को उनके क्षेत्र की अस्मिता एवं विकास कार्यों का तवज्जो दिया गया। यह पहली सरकार रही जिसने जनता के लिए सकारात्मक कार्य किए। लेकिन सरकार के शासनकाल के समय हुए भ्रष्टाचार इस सरकार को पतन की ओर ले जाने का सबसे बड़ा कारण साबित हुए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 संपन्न हुआ। इस गठबंधन को और मजबूत बनाने के लिए आपस में समाजस्य बनने लगे। फिर भी यह चुनाव पिछले चुनाव से अलग दिशा में भारतीय राजनीति को एक बार फिर व्यक्ति केंद्रित राजनीति की ओर ले गया। जिसका परिणाम यह निकला कि श्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इतना बढ़ गया कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी को अपना जमानत बचाने में भी असफल

रहे। इस चुनाव में विपक्ष पार्टी को भी इतना सीट नहीं मिला जो विपक्ष में बैठने के काबिज हो। यह सरकार स्थाई सरकार साबित हुई इस चुनाव में NDAको 336 सीटे जीती जिसमें से भाजपा ने अकेले 282 सीटे प्राप्त किया जिसे पूर्ण बहुमत कहा जाता है। इधर कांग्रेस 44 सीटों पर ही जीत पाई।इस चुनाव में भाजपा को 39 प्रतिशत मत प्राप्त हुआ वही UPA को 24 प्रतिशत वोट ही प्राप्त हुआ।

2019 में 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ था।इस चुनाव को राष्ट्रवाद के नाम पर लड़ा गया। किसी अन्य मुद्दों पर भले ही भारतीय जनता साथ न दे लेकिन जहां राष्ट्रवाद की बात आती है तो वहां पूरा जनता एक मत होकर सरकार के ही पक्ष मे जाती है। भाजपा ने इसका लाभ बखूबी उठाया।पुलवामा हमला एवं बालाकोट जैसी घटनाओं ने जनता को अपनी सुरक्षा को लेकर भावनात्मक रूप से सरकार से जुड़ाव हो गया। भाजपा ने इसी को अपना मुद्दा बना कर प्रचार किया। पहले चाहे जितने भी मुद्दे थे। जैसे बेरोजगारी, लूट ,हत्या ,चोरी, भ्रष्टाचार आदि को भारतीय जनता ने भुला दिया। इसी का अवसर का लाभ भाजपा सरकार को मिला।इस चुनाव में इतनी अधिक सीटो पर जीत हासिल हुई। इस चुनाव में अकेले भाजपा ने 303 सीट पर जीत हासिल हुआ। जो एक पूर्ण बहुमत को प्राप्त होना चाहिए उस से ज्यादा ही प्राप्त किया। NDA को कुल 351 सीट प्राप्त हुई। इस बार कांग्रेस को 52 सिम प्राप्त की इस बार भी विपक्ष में बैठने के लिए न्यूनतम प्रतिशत जो होती है वहां तक पहुंचने में असफल रही विपक्ष पार्टी ।

18वीं लोकसभा चुनाव में कई पार्टियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्य रूप से, दो गठबंधन सामने आए:

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA):इसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने किया।और इस गठबंधन ने बहुमत हासिल किया और सरकार बनाई। इस गठबंधन में कई अन्य क्षेत्रीय दल भी शामिल थे, जैसे कि तेलुगु देशम पार्टी (TDP) और जनता दल (यूनाइटेड) (JD(U))।

भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (INDIA): इसका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने किया। यह मुख्य विपक्षी गठबंधन था। इस गठबंधन में समाजवादी पार्टी (SP), अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC), द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) जैसी पार्टियां शामिल थी।इन मुख्य गठबंधनों के अलावा, कुछ क्षेत्रीय दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों ने भी चुनाव में भाग लिया और कुछ सीटें जीतीं।

संदर्भ सूची

1. डॉ. फारिया बी. एल. एवं डॉ. कुलदीप फारिया, भारतीय शासन एवं राजनीतिक, साहित्य भवन, आगरा, 2019

2. गठबंधन की सरकारें एवं राष्ट्रपति की भूमिका: ओम प्रकाश पवार।

3. बिहार के संदर्भ में गठबंधन सरकार एवं प्रशासन ने: कुमारी सरोज एवं अनिल कुमार ओझा

4. एम लक्ष्मीकांत-भारत की

5. राजव्यवस्था-माइक्रो हिल एजुकेशन लि. न्यू दिल्ली-2014,

6. शर्मा हरिश्चंद्र-भारत में राज्यों की राजनीति, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर 986-87